



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana

No. 1–2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 1, 2019 (PAUSA 11, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 1 जनवरी, 2019

संख्या 02/जीएसठी-2-— चूंकि, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 16 की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित ऐसे बीजकों या बीजक का सम्बन्ध है, की समाप्ति के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, कि देय तिथि के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं होगा ।

और, चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि,—

ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए धारा (1) के अधीन व्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन असुमेलित रहे हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या लोप को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सुधार करेगा और कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा, यदि ऐसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के मद्दे कर का कम भुगतान किया गया है :

परंतु उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए व्यौरों के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे ऐसे व्यौरे सम्बन्धित हैं या सुसंगत वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत किए जाने, इनमें जो भी पहले हो, के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अनुमत नहीं किया जाएगा ;

और, चूंकि, वित्तीय वर्ष 2017–18 भारत में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और करदाता अभी नई कराधान प्रणाली से स्वयं को सुपरिचित कराने की प्रक्रिया में थे और उक्त सुविज्ञता के अभाव के कारण—

- (i) इनपुट कर प्रत्यय के उपभोग के लिए पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर उपधारा (4) में निर्दिष्ट गुम हुए बीजकों या नामे नोटों के कारण धारा 16 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसका दावा नहीं कर सके ;
- (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार त्रुटि या लोप का सुधार नहीं कर सके ;

जिसके परिणामस्वरूप धारा 16 की उपधारा (4) और धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों को प्रभावी करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ;

इसलिए, अब, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (2017 का 19), की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, यह आदेश करते हैं कि—

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के प्रयोजनों हेतु, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तिथि के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक के सम्बन्ध में मार्च, 2019 के मास के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च, 2019 के मास के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि तक अपलोड कर दिए गए हैं।
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के प्रयोजनों हेतु उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर, 2018 के मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च, 2019 के मास या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 की तिमाही के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि तक अनुज्ञात किया जाएगा।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 1st January, 2019

No. 02/GST-2.— WHEREAS, Sub-section (4) of Section-16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) provides that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoices or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND, WHEREAS, Sub-section (3) of Section 37 of the said Act provides that any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or Section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay tax and interest, if any, in case there is short payment of tax on account of such error or omission, in return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under Sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND, WHEREAS, the financial year 2017-18 was the first year of the implementation of the Goods and Services Tax in India and the taxpayers were still in the process of familiarising themselves with the new taxation system and due to lack of said familiarity—

- (i) the registered persons eligible to avail input tax credit could not claim the same in terms of provisions of section 16 because of missing invoices or debit notes referred to in sub-section (4) within the stipulated time;
- (ii) the registered persons could not rectify the error or omission in terms of provisions of Sub-section (3) of section 37 within the stipulated time,

as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of Sub-section (4) of Section 16 and Sub-section (3) of Section 37;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Haryana, on recommendations of the Council, for the purposes of Sections 16 and 37 of the said Act, hereby orders that,—

- (i) In sub-section (4) of Section 16 the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under Section 39 for the month of September, 2018 till the due date

of furnishing of the return under the said section for the month of March, 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or services or both made during the financial year 2017-18, the details of which have been uploaded by the supplier under Sub-section (1) of Section 37 till the due date for furnishing the details under Sub-section (1) of said section for the month of March, 2019;

(ii) In Sub-section (3) of Section 37 the rectification of error or omission in respect of the details furnished under Sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under Section 39 for the month of September, 2018 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) for the month of March, 2019 or for the quarter January, 2019 to March, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

8503—C.S.—H.G.P., Pkl.